RNI No.: UPHIN/25/A1698

NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 258
दि. 19.01.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

सीएम योगी ने यूपी हेल्थटेक कॉन्क्लेव 1.0 का किया उद्घाटन, प्रदेश के हेल्थ सेक्टर का ये खाका खींचा

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को स्वास्थ्य और तकनीक के महासंगम 'यूपी हेल्थटेक कॉन्क्लेव 1.0' का शानदार शुभारंभ हुआ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन दिवसीय इस आयोजन का उद्घाटन करते हुए उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा 'हेल्थकेयर कंज्यूमर मार्केट' करार दिया. सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि यूपी अब केवल बीमारियां ठीक करने वाला राज्य नहीं, बल्कि मेडिकल टेक्नोलॉजी और फार्मा मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है.

25 करोड़ नहीं, 35 करोड़ की जिम्मेदारी

सीएम योगी ने अपने संबोधन में एक महत्वपूर्ण आंकड़ा साझा करते हुए कहा कि यूपी की आबादी भले ही 25 करोड़ है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य ढांचा पड़ोसी राज्यों (बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड) और पड़ोसी देश नेपाल सहित लगभग 35 करोड़ लोगों की चिकित्सा आवश्यकताओं का भार उठा रहा है. हम इस जिम्मेदारी को पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभा रहे हैं.

2017 बनाम 2026: स्वास्थ्य क्षेत्र का कायाकल्प

सीएम योगी ने पिछले पौने नौ वर्षों (2017 से अब तक) के बदलावों को आंकड़ों के जरिए पेश किया:

मेडिकल कॉलेज: 2017 से पहले यूपी में कुल 40 (सरकारी व निजी) मेडिकल कॉलेज थे, जो अब बढ़कर 81 हो चुके हैं.

एम्स और अस्पताल: प्रदेश में 2 एम्स पूरी तरह क्रियाशील हैं और 100 से अधिक जिला अस्पताल सरकारी तौर पर संचालित हो रहे हैं.

ग्रामीण नेटवर्क: सीएचसी , पीएचसी और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की एक मजबूत चेन दूर-दराज के इलाकों तक मुफ्त इलाज पहुंचा रही है.

आयुष्मान योजना: 5.5 करोड़ गोल्डन कार्ड का रिकॉर्ड

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की सफलता का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अब तक 5.5 करोड़ परिवारों को आयुष्मान गोल्डन कार्ड जारी किए जा चुके हैं. इसके तहत हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है. उन्होंने कहा कि जो लोग इस योजना के दायरे में नहीं आ सके, उन्हें 'मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना' या मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सीधे मदद दी जा रही है.

इंसेफेलाइटिस पर जीत और 'जीरो डेथ' का मॉडल

सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहर बरपाने वाली बीमारी इंसेफेलाइटिस (दिमागी बुखार) की चर्चा करते हुए कहा कि पिछले 40 साल में 50 हजार मासूम बच्चों की मौत हुई थी. लेकिन 2017 के बाद हमने इस पर निर्णायक प्रहार किया. आज नतीजा यह है कि यूपी में इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौतों का आंकड़ा शून्य पर पहुंच गया है. इसके साथ ही प्रदेश में संस्थागत प्रसव का ग्राफ अब राष्ट्रीय औसत के बराबर आ चुका है.

मेडिकल डिवाइस पार्क और 'मेक फॉर द वर्ल्ड'

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की औद्योगिक प्रगति का खाका खींचते हुए बताया कि यमुना एक्सप्रेस-वे क्षेत्र में अत्याधुनिक मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जा रहा है. ललितपुर में बल्क ड्रग फार्मा पार्क का काम युद्धस्तर पर जारी है. सीएम योगी ने ने कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ 'आत्मनिर्भर भारत' नहीं, बल्कि 'मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' है, ताकि चिकित्सा उपकरणों के लिए दुनिया की निर्भरता यूपी पर बढ़े.

टेक्नोलॉजी और रिसर्च का नया दौर: वढ-क्टफ्अर लॉन्च

कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने तकनीक की दिशा में दो बड़े कदम उठाए. एक तो वढ-क्टफ्अर सॉफ्टवेयर यानी 'एकीकृत चिकित्सा अनुसंधान अनुप्रयोग प्रणाली' का लोकार्पण किया गया. यह डिजिटल प्लेटफॉर्म क्लिनिकल ट्रायल और मेडिकल रिसर्च को पारदर्शी और पेपरलेस बनाएगा. इसके अलावा क्लिनिकल ट्रायल के लिए 22 प्रकार के मानक संचालन प्रक्रियाओं (रडढर) वाली पुस्तक जारी की गई, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप शोध को बढ़ावा देगी.

निवेशकों को न्योता: यूपी आइए, हम देंगे हर सहयोग

सीएम योगी ने अंत में देश-विदेश के उद्यमियों और स्टार्टअप्स को उत्तर प्रदेश में निवेश का खुला निमंत्रण दिया. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से समयबद्ध स्वीकृतियां और सुरक्षित निवेश वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा. इस कॉन्क्लेव में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य राज्यमंत्री मयंकेश्वर सिंह और केंद्र व राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए. यह आयोजन यूपी को 'ईज ऑफ लिविंग' के साथ-साथ 'ईज ऑफ हीलिंग' का भी केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

एक विकसित भारत के लिए पूर्वी भारत का विकास आवश्यक है : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के सिंगूर में 830 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगूर में 830 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कल वे मालदा में थे और आज उन्हें हुगली की जनता के बीच रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक विकसित भारत के लिए पूर्वी भारत का विकास आवश्यक है और इस लक्ष्य को लेकर केंद्र सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कल और आज के कार्यक्रम इस संकल्प को और मजबूत करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान उन्हें पश्चिम बंगाल के विकास से संबंधित सैकड़ों करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने का अवसर मिला।

श्री मोदी ने बताया कि कल पश्चिम बंगाल से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू की गई। उन्होंने आगे कहा कि बंगाल को लगभग आधा दर्जन नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी मिली हैं। उन्होंने बताया कि आज तीन और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से एक ट्रेन उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी और बंगाल के बीच संपर्क को और मजबूत करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली और तमिलनाडु के लिए भी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 24 घंटे पश्चिम बंगाल के रेल संपर्क के लिए अभूतपूर्व रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंगाल में जलमार्गों की अपार संभावनाएं हैं और केंद्र सरकार इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि बंदरगाह आधारित विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले ही बंदरगाहों और नदी-जलमार्गों से संबंधित परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। उन्होंने जोर दिया कि ये पश्चिम बंगाल और भारत के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि ये वे स्तंभ हैं जिन पर पश्चिम बंगाल को विनिर्माण, व्यापार और रसद के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने इन परियोजनाओं के लिए सभी को बधाई दी।

श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि बंदरगाहों और उनसे जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र पर जितना अधिक ध्यान दिया जाएगा, उतना ही अधिक रोजगार सृजित होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह की क्षमता विस्तार में महत्वपूर्ण निवेश किया है।

जे एण्ड के के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, पाक समर्थित जैश के 3 आतंकियों को सेना ने घेरा

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के सिंहपोरा में रविवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ से इलाके में तनाव फैल गया। यह मुठभेड़ सिंहपोरा क्षेत्र में उस समय शुरू हुई, जब सुरक्षाबल आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर सघन तलाशी अभियान चला रहे थे।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस मुठभेड़ में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकवादियों के शामिल होने की आशंका है।

सरकार गोला-बारूद के निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने और देश को वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध

(जीएनएस)।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की गोला-बारूद निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने और देश को इस क्षेत्र में वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। 19 जनवरी, 2026 को नागपुर, महाराष्ट्र में सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड में मध्यम कैलिबर गोला-बारूद निर्माण सुविधा का उद्घाटन करते हुए, उन्होंने उस समय को याद किया जब गोला-बारूद की कमी ने देश की रक्षा तैयारियों को बाधित किया था और सरकार ने इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता को महसूस किया था।

एक काले रंग के बोर्ड के सामने खड़े पुरुषों का एक समूह (विवरण स्वचालित रूप से उत्पन्न हुआ)

रक्षा मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया यह संयंत्र पूरी तरह से स्वचालित है और इसमें 30 मिमी गोला बारूद का निर्माण होता है, जिसका उपयोग भारतीय सेना और नौसेना द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है। उन्होंने पिनाका रॉकेट निर्माण संयंत्र का भी दौरा किया और निर्देशित पिनाका रॉकेटों की पहली खेप आर्मेनिया को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में निजी क्षेत्र के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय गोला-बारूद के निर्माण के कारण देश गोला-बारूद उत्पादन में लगातार प्रगति कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से 2021 में भारतीय सेना को निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पूर्णतः भारतीय गोला-बारूद मल्टी-मोड हैंड ग्रेनेड सौंपे जाने का उल्लेख किया। उन्होंने आगे कहा कि सोलर ग्रुप द्वारा निर्मित नागास्त्र ड्रोन का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सफलतापूर्वक उपयोग किया गया, क्योंकि इसने आतंकवादी ठिकानों पर सटीक प्रहार करके अपनी रणनीतिक क्षमता साबित की।

उन्होंने नागास्त्र के अधिक उन्नत संस्करणों के विकास की सराहना करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर ये हथियार देश के शत्रुओं के लिए अत्यंत घातक साबित होंगे।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सोलर कंपनी द्वारा विकसित किए जा रहे 'भार्गवस्त्र' काउंटर ड्रोन सिस्टम का सफल परीक्षण निजी क्षेत्र की तकनीकी क्षमताओं को दशार्ता है। उन्होंने आगे कहा कि इस संयंत्र में विकसित पिनाका मिसाइलों का निर्यात शुरू हो चुका है, जो देश की निर्यात क्षमता को और मजबूत करने में रक्षा उद्योग की क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल आयातक नहीं, बल्कि तेजी से निर्यातक बनने की ओर अग्रसर है।

रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को राष्ट्र के लिए आत्मनिर्भरता के महत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध लगातार जटिल होते जा रहे हैं, जिसके लिए राष्ट्र को युद्ध स्तर पर तैयार रहना आवश्यक है। उन्होंने कहा, ह्युद्ध के नए तरीके सामने आ रहे हैं। युद्ध अब सीमाओं तक सीमित नहीं हैं। ऊर्जा, व्यापार, शुल्क, आपूर्ति श्रृंखला, प्रौद्योगिकी और सूचना जैसे क्षेत्र भी संघर्ष के नए आयाम बन गए हैं। सीमा सुरक्षा और नवीनतम हथियारों एवं प्रौद्योगिकियों का महत्व बढ़ गया है। युद्ध की प्रकृति चाहे जो भी हो, एक मजबूत रक्षा औद्योगिक आधार की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। ऐसे में विनिर्माण और अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी समय की मांग है।'

एक व्यक्ति फूलों से सजे मंच पर भाषण दे रहा है। (विवरण स्वचालित रूप से उत्पन्न हुआ)

श्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार रक्षा विनिर्माण में निजी क्षेत्र की भूमिका को आगामी समय में 50% या उससे अधिक तक पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र की क्षमताएं और नवाचार इसकी पूर्ण क्षमता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह लक्ष्य जल्द ही प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा, ह्सरकार निजी क्षेत्र को मजबूत करने और घरेलू विक्रेताओं को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमने अपने प्लेटफॉर्म, सिस्टम और सबसिस्टम को धीरे-धीरे स्वदेशी बनाने का निर्णय लिया है। यहां तक कि जिन चीजों का हम निर्माण नहीं कर सकते, उनके लिए भी कम से कम 50% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान किया गया है।

दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का उद्घाटन

(जीएनएस)।

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने आज सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली में आयोजित पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम में इराक और रवांडा के राजदूतों, एमएसएमई मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों, कारीगरों तथा अन्य हितधारकों ने भी अपनी उपस्थिति से समारोह की शोभा बढ़ाई।

सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने पीएम विश्वकर्मा योजना की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और प्रदर्शनी के सफल आयोजन के लिए टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि

ह्पीएम विश्वकर्मा गांव-स्तरीय पृष्ठभूमि से आने वाले कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान करता है और यह एक सराहनीय प्रयास है।' केंद्रीय मंत्री ने विश्वकर्मा के महत्व को भी स्पष्ट किया और योजना के पीछे की परिकल्पना की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सफल और गतिशील नेतृत्व में यह योजना देश के प्रत्येक विश्वकर्मा को बाजारों तक पहुंच प्रदान कर रही है और उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान देने का अवसर दे रही है।

इस अवसर पर बोलते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि, ह्प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में पीएम विश्वकर्मा पहल ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। पीएम विश्वकर्मा हाट के मंच पर विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 117 से अधिक कारीगरों की भागीदारी देखना वास्तव में उत्साहजनक है।' उन्होंने आगे कहा कि पीएम विश्वकर्मा गांव के कारीगरों को एक सक्षम मंच प्रदान कर उनसे जुड़ाव स्थापित करता है, जिससे उनके लिए वैश्विक बाजारों तक पहुंच के नए मार्ग खुलते हैं। उनके अनुसार, ये उपलब्धियां भारत सरकार के सतत प्रयासों और एमएसएमई मंत्रालय के समर्पित कार्य का परिणाम हैं।

वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी ने काशी विश्वनाथ और काल भैरव के किए दर्शन

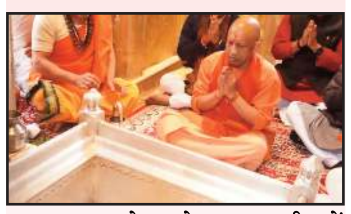

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर और काशी कोतवाल काल भैरव मंदिर में दर्शन और पूजन किया. वह चंदौली में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीधे वाराणसी पहुंचे. नए वर्ष में यह मुख्यमंत्री का दूसरा वाराणसी दौरा रहा.

मुख्यमंत्री ने काल भैरव मंदिर और श्री काशी विश्वनाथ धाम में विधिवत पूजन अर्चन कर प्रदेश और देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की. उन्होंने लोक कल्याण की कामना करते हुए श्रद्धालुओं का अभिवादन भी किया. मंदिर परिसर में मौजूद बच्चों से बातचीत की और उन्हें चॉकलेट दी.

दर्शन के दौरान मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में शांतिपूर्वक

लक्षद्वीप के द्वीपों में संयुक्त सेवाओं का मल्टी-स्पेशियलिटी मेडिकल कैंप का समापन

(जीएनएस)।

भारतीय नौसेना ने 16 जनवरी 2026 को लक्षद्वीप के द्वीपों में पांच दिवसीय संयुक्‍त सेवा मल्टी-स्पेशियलिटी मेडिकल कैंप का सफलतापूर्वक समापन किया। कावारत्ती, अगात्ती, अमीनी, एंड्रोथ और मिनिकॉय द्वीपों पर आयोजित इस कैंप ने बिना किसी रुकावट के इंटर-सर्विसेज सहयोग के जरिए दूरदराज के द्वीपीय समुदायों को अच्छी क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवा और निवारक सेवाएं देने के लिए सशस्त्र बलों की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

इस कैंप को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, 4,719 मरीजों ने स्पेशलिस्ट और सुपर-स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से सलाह ली। लक्षद्वीप में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें स्पेशलिस्ट और सुपर-स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एक बड़ी श्रृंखला उपलब्ध थी, जिससे एडवांस्ड हेल्थकेयर तक पहुंच में काफी सुधार हुआ। टीम में न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के एक्सपर्ट शामिल थे, जिन्हें मेडिसिन, सर्जरी, ईएनटी, ऑप्थल्मोलॉजी, डमेटीलॉजी, डेंटल सर्जरी, रेडियोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का सपोर्ट मिला।

मेडिकल टीमों और उपकरणों की तेजी से तैनाती, साथ ही हर द्वीप पर पूरी तरह से काम करने वाली मेडिकल सुविधाओं की स्थापना ने तीनों सेनाओं के बीच उच्च स्तर के तालमेल और एकजुटता को दिखाया। कर्मियों और संवेदनशील मेडिकल उपकरणों की योजनाबद्ध एयरलिफ्ट और सीलिफ्ट ने प्रभावी इंटर-सर्विसेज तालमेल का प्रदर्शन किया।

सभी द्वीपों पर व्यापक मेडिकल और सर्जिकल सेवाएं प्रदान की गईं। कुल 51 सामान्य सर्जिकल प्रक्रियाएं की गईं।

जिससे भूमि के मुख्य अस्पतालों में रेफरल की आवश्यकता कम हो गई। नेत्र विज्ञान में, 71 मोतियाबिंद सर्जरी की गईं, जिससे कई बुजुर्ग मरीजों की रोशनी वापस आ गई। उन्नत डायग्नोस्टिक्स में 50 से अधिक एंडोस्कोपिक प्रक्रियाएं, 50 से अधिक इकोकार्डियोग्राफिक जांच और कार्डियक मूल्यांकन के लिए कई ट्रेडमिल टेस्ट शामिल थे। रेडियोलॉजी सेवाओं में 250 से अधिक अल्ट्रासाउंड जांच दर्ज की गईं, जबकि 100 से अधिक डेंटल प्रक्रियाएं और 30 से अधिक छोटी त्वचा संबंधी प्रक्रियाएं की गईं। सभी सेवाएं और दवाएं मुफ्त में प्रदान की गईं।

एक स्थायी योगदान के तौर पर, भारतीय नौसेना ने अगाती और अमीनी में हेल्थकेयर सुविधाओं को दो ईसीजी मशीनें दान कीं। निवारक स्वास्थ्य,

प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की

प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हो गई। अफसरों से भी झड़प हुई। इसके बाद पुलिस ने शिष्यों को दौड़ाकर पकड़ लिया और उन्हें हिरासत में ले लिया। एक साधु को पुलिस ने चौकी में गिरा-गिराकर पीटा।

इसके बाद शंकराचार्य नाराज हो गए और शिष्यों को छुड़वाने पर अड़ गए। उन्हें अफसरों ने समझाने की हर कोशिश की, हाथ जोड़े, लेकिन वे नहीं माने। करीब 2 घंटे तक गहमा-गहमी चलती रही। इसके बाद पुलिस ने शंकराचार्य के सभी समर्थकों को हिरासत में ले लिया।

बाद में शंकराचार्य की पालकी को खींचते हुए संगम से 1 किमी दूर ले जाया गया। इस दौरान पालकी का क्षत्रप भी टूट गया। शंकराचार्य स्नान भी नहीं कर पाए। विवाद की शुरूआत में पुलिस ने भीड़ को देखते हुए शंकराचार्य को रथ से उतरकर पैदल जाने को कहा था, लेकिन शिष्य नहीं माने और आगे बढ़ने लगे। इस पर बहस हुई, फिर देखते ही देखते धक्का-मुक्की शुरू हो गई।

शंकराचार्य ने कहा कि, बड़े-बड़े अधिकारी हमारे संतों को मार रहे थे। पहले तो हम लौट रहे थे, लेकिन अब स्नान करेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। वे हमें रोक नहीं पाएंगे।

इनको ऊपर से आदेश होगा कि इन्हें परेशान करो। यह सरकार के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि वे हमसे नाराज हैं। जब महाकुंभ में भगदड़ मची थी, तो मैंने उन्हें जिम्मेदार ठहराया था। अब वे बदला निकालने के लिए अधिकारियों से कह रहे होंगे।

रायबरेली-ऊंचाहार मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में उमड़ा युवाओं का उत्साह, एसडीएम ने परखी व्यवस्थाएं

रायबरेली-ऊंचाहार मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में उमड़ा युवाओं का उत्साह, एसडीएम ने परखी व्यवस्थाएं

(जीएनएस)।

ऊंचाहार (रायबरेली)। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में रायबरेली जिले के ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के अंतर्गत 'विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026' पूरी सक्रियता के साथ संचालित किया जा रहा है। रविवार को अवकाश का दिन होने के बावजूद तहसील के खोजनपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों में नए मतदाताओं में सूची में नाम जुड़वाने को लेकर अभूतपूर्व उत्साह

देखने को मिला। विशेषकर पहली बार मतदाता बनने जा रहे युवाओं ने भारी संख्या में शिविरों में पहुँचकर अपनी लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उत्साह दिखाया।

इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य 1 जनवरी 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों (वोटर लिस्ट) को पूरी तरह अपडेट और त्रुटिहीन बनाना है। इसे लेकर तहसील प्रशासन पूरी तरह गंभीर नजर आ रहा है। क्षेत्र के अलग-अलग विद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष शिविर लगाए गए हैं, जहाँ बीएलओ (इछड) द्वारा नाम जोड़ने और संशोधन का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।

प्रशासनिक मुस्तैदी का जायजा लेने के लिए रविवार को उपजिलाधिकारी (एसडीएम) राजेश कुमार श्रीवास्तव ने स्वयं मोर्चा संभाला। उन्होंने पूरब गाँव में आयोजित विशेष शिविर का औचक निरीक्षण किया और बीएलओ के रजिस्टर व अब तक प्राप्त हुए आवेदनों की बारीकी से जांच की। एसडीएम के निर्देशों के क्रम में नायब तहसीलदार शम्भू शरण पाण्डेय और लेखपाल प्रमोद गुप्ता ने भी क्षेत्र के विभिन्न बूथों का सघन निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

एसडीएम राजेश कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि यह विशेष अभियान 06 जनवरी 2026 से शुरू हुआ है और 06 फरवरी 2026 तक निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने क्षेत्र की जनता, विशेषकर युवाओं से अपील की कि जिनकी आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, वे अपना नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं। इसके साथ ही, सूची में नाम जोड़ने, विलोपित करने या किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए भी आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। एसडीएम ने बीएलओ और सभी लेखपाल सुपरवाइजरों को कड़ी हिदायत दी है कि कार्य में पूर्ण पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रहे।

मादक द्रव्यों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान को और अधिक गति दी गई

लखनऊ

एसीपी महानगर अंकित कुमार के निर्देशन एवं थाना प्रभारी महानगर अखिलेश कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में मादक द्रव्यों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान को और अधिक गति दी गई..

इस क्रम में चौकी इंचार्ज निशातगंज सत्येंद्र कुमार, चौकी इंचार्ज न्यू हैदराबाद अरुण सरोज,गोल मार्केट चौकी इंचार्ज आर्यन शर्मा, उपनिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद सहित महानगर पुलिस टीम ने मेवा नर्सरी सोसाइटी क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए नशा नियंत्रण को लेकर सघन कार्रवाई की..

अभियान के दौरान पुलिस ने स्थानीय नागरिकों से संवाद स्थापित कर उन्हें अभियान की प्रगति से

अवगत कराया और सहयोग की अपील की। पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया कि नशा कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा..

पुलिस की इस पहल से क्षेत्रवासियों में सुरक्षा और विश्वास का माहौल और अधिक मजबूत हुआ है..

राजकुमार राव और पत्रलेखा ने अल्फा जेन बेटी का रखा ऐसा नाम, जिसे जान उनके फैंस भी हो जाएंगे गदगद

(जीएनएस)।

राजकुमार राव और पत्रलेखा ने अपनी निजी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत खुशखबरी साझा करते हुए अपनी बेटी के नाम का ऐलान कर दिया है। इस सेलिब्रिटी कपल ने इंस्टाग्राम पर अपनी नन्ही परी की पहली भावनात्मक झलक साझा की और बताया कि उनकी बेटी का नाम 'पर्वती पॉल राव' रखा गया है। इस पोस्ट के साथ ही दोनों ने अपने प्रशंसकों को माता-पिता बनने की अपनी सबसे बड़ी खुशी से रूबरू कराया।

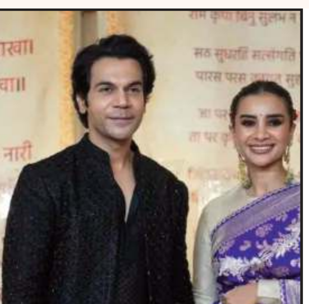

साझा की गई तस्वीर बेहद सादगी और भावनाओं से भरी हुई है। फोटो में बच्ची का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसकी छोटी-सी उंगलियां अपने माता-पिता की उंगलियों को थामे हुए नजर आ रही हैं। यह दृश्य नए माता-पिता के बीच बने गहरे रिश्ते और प्रेम को दशार्ता है। तस्वीर की कोमलता और भावनात्मक गहराई ने प्रशंसकों का दिल जीत लिया है।

इस तस्वीर के साथ राजकुमार और पत्रलेखा ने लिखा, "हाथ जोड़कर और पूरे दिल से, हम अपने सबसे बड़े आशीर्वाद का परिचय कराते हैं।" इसके साथ उन्होंने अपनी बेटी का नाम 'पर्वती पॉल राव' बताते हुए दिल और प्रार्थना वाले इमोजी जोड़े, जिसने इस पल को और भी खास बना दिया।

'पर्वती' नाम भारतीय परंपरा में शक्ति, करुणा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। वहीं 'पॉल' और 'राव' दोनों माता-पिता के पारिवारिक नामों को दशार्ते हैं। नाम के ऐलान के साथ ही सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई कलाकारों और प्रशंसकों ने इस जोड़े को ढेरों शुभकामनाएं दीं।

राजकुमार राव और पत्रलेखा ने नवंबर 2025 में अपनी बेटी का स्वागत किया था। खास बात यह है कि उनकी बेटी ने दुनिया में कदम उनकी चौथी शादी की सालगिरह के दिन रखा। कपल ने उस समय लिखा था कि ईश्वर ने उन्हें इस खास दिन पर सबसे बड़ा उपहार दिया है और वे इस खुशी से अभिभूत हैं।

दोनों की प्रेम कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सालों पहले मुलाकात के बाद उनका रिश्ता धीरे-धीरे गहराता गया। 2014 में फिल्म 'सिटीलाइट्स' के दौरान उनका रिश्ता मजबूत हुआ और नवंबर 2021 में उन्होंने शादी कर ली।

गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर, वायुसेना स्टेशन, चांदीनगर में मैरून बेरेट की औपचारिक परेड

(जीएनएस)।

1. वायु सेना के 'गरुड़' बल के विशेष बलों के कर्मियों के प्रशिक्षण के सफल समापन के उपलक्ष्य में, गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर (जीआरटीसी), वायु सेना स्टेशन चांदीनगर में 17 जनवरी 2026 को मैरून बेरेट औपचारिक परेड का आयोजन किया गया। वायु सेना संचालन के सहायक प्रमुख (वायु रक्षा) ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में परेड का निरीक्षण किया।

2. गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर के कमांडेंट ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और उन्हें प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। मुख्य अतिथि ने गरुड़ कमांडो को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर बधाई दी। युवा कमांडो को संबोधित करते हुए उन्होंने तेजी से बदलते सुरक्षा परिदृश्य के अनुरूप कठोर प्रशिक्षण और विशेष बलों के कौशल को निखारने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सफल गरुड़ प्रशिक्षुओं को मैरून बेरेट, गरुड़ प्रोफिशिएंसी बैज और विशेष बल टैब प्रदान किए और पुरस्कार विजेताओं को ट्राफियां दी।

3. पासिंग आउट समारोह के दौरान, 'गरुड़ कमांडो' ने युद्धक फायरिंग, बंधकों के बचाव, फायरिंग ड्रिल, विस्फोटक सामग्री पर हमला, बाधा पार करना, दीवार पर चढ़ना, रेंगना, रस्सियों से उतरना और सैन्य मार्शल आर्ट जैसे विभिन्न कौशल का प्रदर्शन किया।

4. मैरून बेरेट औपचारिक परेड 'गरुड़ कमांडो' के लिए गौरव और उपलब्धि का क्षण है। यह एक अत्यंत कठिन प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन है और विशिष्ट 'गरुड़' बल में शामिल 'युवा विशेष बल संचालकों' के रूप में उनके परिवर्तन का प्रतीक है।

5. ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायु सेना के विशेष बलों की भूमिका को देखते हुए, हाल ही में उत्तीर्ण हुए विशेष बल संचालक नवपरिभाषित विशेष अभियानों को अंजाम देने के लिए भारतीय वायु सेना की क्षमता को और मजबूत करेंगे।

भाजपा सरकार ने अरविंद केजरीवाल का कार्यक्रम स्थल रद्द करवाया : गोपाल इटालिया

(जीएनएस)।

जहां कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाला था, वहां की अनुमति सरकार ने रद्द की : गोपाल इटालिया

रात के अंधेरे में पुलिस ने कार्यक्रम स्थल पर छापा मारा : गोपाल इटालिया

कार्यक्रम स्थल के मालिक को धमकी दी गई : गोपाल इटालिया

AAP की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा डर गई है : गोपाल इटालिया

AAP का बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन अब दूसरी जगह होगा : गोपाल इटालिया

अब कार्यक्रम अहमदाबाद के नरोडा-निकोल की बजाय साणंद के लोदरियाल गांव में आयोजित होगा : गोपाल इटालिया

अहमदाबाद / गुजरात

आम आदमी पार्टी के विसावदर से विधायक गोपाल इटालिया ने पत्रकार परिषद में बताया कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की प्रेरक उपस्थिति में अहमदाबाद के निकोल क्षेत्र में बूथ कार्यकताओं की बैठक आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम की सभी तैयारियां लगभग 20 से 25 दिन पहले पूरी कर ली गई थीं। कार्यक्रम के लिए निजी पार्टी प्लॉट बुक किया गया था, पुलिस को पहले से सूचना दी गई थी तथा साउंड, कुर्सियों सहित सभी व्यवस्थाएं तय कर ली गई थीं। लेकिन अंतिम समय में भाजपा के लोगों द्वारा पार्टी प्लॉट के मालिक को धमकी और दबाव दिए जाने के कारण कार्यक्रम रद्द करवा दिया गया। पुलिस भेजकर क्षेत्र में भय का माहौल बनाया गया, जो लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।

विधायक गोपाल इटालिया ने आगे कहा कि भारत के प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने कार्यक्रम आयोजित करने का संवैधानिक अधिकार है। आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और गुजरात में 42 लाख से अधिक लोगों ने पार्टी को वोट दिया है। जनता द्वारा चुनी गई विपक्षी पार्टी के लोकतांत्रिक अधिकारों पर इस तरह दबाव बनाना अनुचित है। अब अरविंद केजरीवाल जी का कार्यक्रम साणंद के लोदरियाल गांव में शाम 4 बजे आयोजित होगा। भाजपा हमारे नेताओं को जेल भेजे या कार्यक्रम रद्द करवाए, इससे हम डरने वाले नहीं हैं।

आम आदमी पार्टी गुजरात

जनहित में अनुकरणीय पहलः सेवार्थम फाउंडेशन ने जरूरतमंदों को दिया सहारा

सुल्तानपुर लम्भुआ अर्जुनपुर।

आज के दौर में जब सरकारी योजनाएं भी कई बार जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पातीं, ऐसे समय में सेवार्थम फाउंडेशन द्वारा किया गया सेवा कार्य समाज के लिए मिसाल बनकर सामने आया है। डॉ. आशीष तिवारी के प्रेरणा व मार्गदर्शन में शनिवार, 18 जनवरी 2026 को अर्जुनपुर में आयोजित कार्यक्रम में जरूरतमंद और असहाय लोगों को कान की मशीन (हियरिंग एड) एवं मच्छरदानी का निःशुल्क वितरण किया गया।

यह कार्यक्रम अर्जुनपुर पेट्रोल पंप के पास स्थित आदित्य इंटरप्राइजेज एंड फर्नीचर्स परिसर में प्रातः 10 बजे संपन्न हुआ। इस पहल से जहां एक ओर बुजुर्गों और दिव्यांगों को सुनने की नई उम्मीद मिली, वहीं मच्छरदानी वितरण से गरीब परिवारों को बीमारियों से बचाव का सहारा भी मिला।

कार्यक्रम में मौजूद स्थानीय नागरिकों और समाजसेवियों ने कहा कि ऐसी पहलें ही असल मायनों में जनता के हित में होती हैं, जो सीधे जरूरतमंद तक मदद पहुंचाती हैं। सेवार्थम फाउंडेशन के इस प्रयास ने यह साबित किया कि अगर नीयत साफ हो तो सीमित संसाधनों में भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।

फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि संस्था आगे भी स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करती रहेगी। जनहित में किया गया यह प्रयास न सिर्फ सराहनीय है, बल्कि अन्य सामाजिक संगठनों के लिए भी प्रेरणा है।

सांसद राम भुआल निषाद ने सुल्तानपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में की सहभागिता

जनसेवा मेरा कर्तव्य नहीं, जीवन का उद्देश्य है सांसद

लम्भुआ सुल्तानपुर

सुल्तानपुर।माननीय सांसद राम भुआल निषाद ने अपने संसदीय लोकसभा क्षेत्र सुल्तानपुर के दौरे के दौरान विभिन्न जनहित व सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता की। जनपद आगमन पर कार्यकताओं व समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। सांसद ने मिले स्नेह व अपनत्व के लिए जनता के प्रति आभार व्यक्त किया।

सांसद राम भुआल निषाद ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस (डाक बंगला) सुल्तानपुर में देवतुल्य जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।

इसके उपरांत ग्राम पंचायत बेलहरी के ग्राम रेवारी में समाजवादी क्रांतिकारी रणविजय यादव उर्फ 'हीरो

गांधी' की पुण्यतिथि पर पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सांसद ने कहा कि हीरो गांधी जी का जीवन संघर्ष, सिद्धांत और जनसेवा को समर्पित रहा, जिसे समाजवादी परिवार सदैव स्मरण रखेगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सांसद ने विधानसभा जयसिंहपुर के बरौसा स्थित गिरधारी लाल स्टेडियम पहुंचकर क्रिकेट टूनार्मेंट का रिबन काटकर उद्घाटन किया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। वहीं विधानसभा लंभुआ के रामपुर कुर्मियांन में भी क्रिकेट टूनार्मेंट का उद्घाटन करते हुए खिलाड़ियों को संबोधित किया।

सांसद ने कहा कि खेल जीवन में आनंद और उत्साह का संचार करते हैं। खेल शरीर को स्वस्थ, मन को मजबूत और आत्मा को प्रसन्नता से भर देते हैं।

दौरे के अंत में सांसद राम भुआल निषाद ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस सुल्तानपुर में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों एवं जनहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।

60 घर अंधेरे में, कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना

लम्भुआ (सुलतानपुर)।

परसरामपुर क्षेत्र के कृष्णा नगर में बिजली विभाग की गंभीर लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। यहां बीते 7 दिनों के भीतर तीन बार ट्रांसफार्मर फूंक चुका है, लेकिन इसके बावजूद विभाग ने अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, पूरे मोहल्ले की बिजली सप्लाई पूरी तरह जर्जर तारों के भरोसे चल रही है। ये तार वर्षों पुराने, झूलते हुए और क्षमता से अधिक लोड झेल रहे हैं। इसी कारण बार-बार ट्रांसफार्मर जल रहा है, लेकिन विभाग हर बार सिर्फ ट्रांसफार्मर बदलकर औपचारिकता निभा रहा है।

स्थिति यह है कि करीब 60 परिवार लगातार अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की परेशानी और रोजमर्रा का जीवन

पूरी तरह प्रभावित हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि एक दिन पहले तो गांव बाल-बाल आग लगने की बड़ी घटना से बचा, चिंगारी गिरते ही लोग दहशत में आ गए थे।

स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन न तो जर्जर तार बदले गए और न ही लाइन को सुरक्षित किया गया। लोगों का आरोप है कि विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है।

ग्रामीणों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही जर्जर तारों को बदलकर सुरक्षित लाइन नहीं डाली गई, तो वे मजबूरन विभागीय कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन करेंगे। सूर्य प्रताप यादव अजय यादव राम अवध यादव राम आशीष यादव रामाशंकर यादव सुरेश यादव पवन यादव श्याम लाल यादव रामदयाल यादव रामकुमार यादव रामचंद्र यादव

ऐशबाग पीली कॉलोनी चौराहे पर जल संकट

लखनऊ के पीली कॉलोनी चौराहे पर शिव पार्वती मंदिर के पास रोड पर बह रहा है जल। यह समस्या महीनों से चल रही है, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हो पाया है।

जल ही जीवन, लेकिन नसीब नहीं

लोक कहते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन यहां तो पानी ही नसीब नहीं हो रहा है। घर-घर पानी की समस्या है, लेकिन रोड पर बह रहा है लीकेज का पानी।

ऐशबाग में जलकल का ऑफिस, लेकिन समस्या का समाधान नहीं

ऐशबाग में जलकल का ऑफिस है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। लोगों ने पार्षद और जलकल से शिकायत की है,लेकिन समस्या जैसी थी वैसे ही बनी हुई है।

वाटर लाइन बिछाई गई, लेकिन लीकेज की समस्या

कुछ समय पहले ही वाटर लाइन

बिछाई गई है, लेकिन लीकेज की वजह से हजारों लीटर पानी रोड पर बह रहा है। जलकल विभाग के बड़े-बड़े अधिकारी इसी रोड से निकलते हैं, लेकिन उन्हें यह समस्या नहीं दिखती।

जनता की पुकार

लोग कहते हैं कि जलकल विभाग के अधिकारी इसी रोड से होते हुए निकल रहे पर जमीन से निकल रहे पानी के लीकेज को नहीं देख रहे हैं। अब इस समस्या का समाधान कितनी जल्दी होता है, यह देखने का विषय है।

निवेदन

हम जलकल विभाग से अनुरोध करते हैं कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। जनता को पानी की समस्या से निजात दिलाई जाए।

- जलकल विभाग के अधिकारियों को इस समस्या का समाधान करना चाहिए
- वाटर लाइन की जांच की जानी चाहिए
- लीकेज की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए
- जनता को पानी की समस्या से निजात दिलाई जानी चाहिए

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

डब्ल्यूईएफ की चुनौतियां

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक सोमवार से स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में शुरू होने जा रही है। इस बैठक में दुनिया के लगभग 80 राष्ट्राध्यक्ष, राजनेताओं और उद्योगपतियों सहित 3000 से अधिक लोगों की मौजूदगी संभावित है। इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होंगे। इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ऊर्जा पर चर्चा होने की संभावना है किन्तु सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इसी बैठक में इस विषय पर भी चर्चा होनी है कि 'क्या भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है।' भारत ने भी इस बैठक में शामिल होने के लिए एक दमदार टीम भेजी है जिसमें चार वेंद्रीय वैबिनेट मंत्री शिवराज सिह चौहान, अश्विनी वैष्णव, प्राह्लाद जोशी और राममोहन नायडू शामिल होंगे। इनके अलावा 6 मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस, हिमंत विश्व शर्मा, मोहन यादव, चंद्रबाबू नायडू, रेवन्त रेड्डी और हेमन्त सोरेन शामिल हैं। इस बैठक में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिव वुमार के शामिल होने की बात की जा रही है। इस टीम की विशेष बात यह है कि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और 100 के करीब भारतीय उद्योगों के मुख्य कार्यकारी भी शामिल होंगे। इनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी भी शामिल हैं। इस बैठक में शामिल होने वाले 180 देशों में से जो विकसित देश हैं, उनके आर्थिक हित, विकासशील देशों के आर्थिक हितों से बिल्वुल भिन्न हैं। सच तो यह है कि विकसित देशों के आर्थिक हित विकासशील देशों के शोषण पर निर्भर होते हैं। ये विकसित देश जो खुद करते हैं, उसे न करने के लिए ही विकासशील देशों को नसीहत देते हैं। अपने किसानों को सब्सिडी देने वाले अमेरिका को यह नहीं अच्छा लगता कि विकासशील देश भी अपने किसानों को सब्सिडी दें या किसी भी तरह की सुरक्षा दें। ये विकसित देश इतने ढोंगी हैं कि विकासशील और अर्ध विकसित देशों पर दबाव डालते हैं कि वे अपने देश के उद्योगों में प्रातिस्पर्धा बढ़ाने के लिए उन्हें किसी भी तरह की सुरक्षा की गारंटी न दें। यही नहीं ये विकसित देश वैश्विक आर्थिक संस्थानों से कर्ज दिलाने की लालच तो देते हैं किन्तु साथ ही यह भी सुनिाित कर देते हैं कि विकासशील एवं अर्ध विकसित देश अपने देश में सभी तरह के उपभोक्ता टैक्स बढ़ा दें। मतलब यह कि विकासशील और अर्ध विकसित देश अपने देश की जनता को टैक्स के बोझ से दबा दें और विकसित देश तमाशा देखें। बड़ी हैरानी होती है कि जब जरूरतमंद देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्व बैंक एवं अन्य क्षेत्रीय विकास बैंकों से कर्ज लेते हैं तो उन पर तमाम ऐसी शर्ते थोप दी जाती हैं जो विकसित देशों के हितों के अनुरूप थोप दी जाती हैं।

बहरहाल भारत की टीम में अनुभवी राजनेता भाजपा और कांग्रोस के अलावा तेलगूदेशम और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे क्षेत्रीय पार्टियों के भी शामिल हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सभी टीम इंडिया की भावना से भारतीय किसानों, व्यवसायियों, विद्यार्थियों एवं सामान्य जन के हितों के लिए, सफलता के लिए हरसंभव प्रायास करेंगे। लगता है कि इस बार अमेरिका हमेशा की तरह यूरोपीय देशों का समर्थन हासिल नहीं कर पाएगा क्योंकि अब यूरोपीय यूनियन यह अच्छी तरह समझ चुका है कि अमेरिका को उनके हितों की नहीं बल्कि अपने हितों की चिन्ता है जो पूरी दुनिया को शिकार बनाने पर तुला है। यही कारण है कि इस बार अमेरिकी शोषण की प्रावृत्ति को आइना दिखाने में आसानी होगी। भारतीय टीम अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा करने में सफल होगी।

'भाजपा नंबर 1 पार्टी', मुंबई मेयर पद को लेकर चल रही खींचतान के बीच एकनाथ शिंदे के बयान ने बढ़ाया सस्पेंस

(जीएनएस)।

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बड़ी जीत हासिल की है। भाजपा ने मुंबई महानगरपालिका (BMC) में 89 सीटें जीतीं। वहीं, सहयोगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 29 सीटें मिलीं, जबकि उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को महज 3 सीटें ही हासिल हो पाईं। इस चुनाव में महायुति की बड़ी जीत के बाद मुंबई में 'रिसॉर्ट की राजनीति' फिर लौट आई है। 29 सीटें जीतने वाले एकनाथ शिंदे खेमे ने अपने पार्षदों को मुंबई के एक पांच सितारा होटल में दो दिनों से रखा है जिससे तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही थी।

भाजपा को 'नंबर एक पार्टी'

मेयर पद को लेकर चल रहे सस्पेंस के बीच रविवार को उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया है। बीएमसी चुनावों के बाद दिए गए इस बयान में उन्होंने भाजपा को 'नंबर एक पार्टी' बताया। शिंदे ने कहा कि बालासाहेब ठाकरे के आशीर्वाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के दम पर शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) कम समय में ही एक मजबूत दल के रूप में उभरी है।

जीते हुए पार्षदों से क्या बोले शिंदे?

एकनाथ शिंदे के अनुसार, अब तक हुए चुनावों में उनकी पार्टी दूसरे स्थान पर रही है, जो आगामी चुनावों की एक महत्वपूर्ण भूमिका तय करती है। उन्होंने नव-निर्वाचित नगरसेवकों से कहा कि वे अपने-अपने प्रभाग की जिम्मेदारी गंभीरता से निभाएं और सक्रिय रूप से जनता के बीच जाकर काम करें।शिंदे ने पार्षदों को नसीहत देते हुए साफ कहा कि उनके व्यवहार और बोलचाल पर नागरिकों की पैनी नजर रहती है। ऐसे में किसी भी प्रकार की गलती या आरोप से बचने का ध्यान रखना चाहिए।

मुंबई का मेयर कौन होगा?

इसके साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मुंबई का अगला मेयर 'महायुति' से होगा। उन्होंने बताया कि सोमवार (18 जनवरी) को गट का औपचारिक गठन किया जाना है, और वे सभी सदस्यों से मिलने वाले हैं। इससे पहले, उन्होंने चुने हुए नगरसेवकों के साथ बैठक की, जिसमें मुंबई के विकास की रणनीतियों पर विशेष चर्चा हुई।

शिंदे शिवसेना ने पार्षदों को क्यों होटल में ठहराया है?

बता दें शिवसेना (शिंदे गुट) के नवनिर्वाचित पार्षदों को एक होटल में ठहराया गया है, जिस पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) ने आरोप लगाया है कि पार्षदों को 'बंधक' बनाया जा रहा है। इन आरोपों पर शिंदे गुट ने अपनी सफाई दी है। शिवसेना प्रवक्ता शीतल म्हात्रे ने स्पष्ट किया कि पार्षदों को बंधक नहीं बनाया गया है, बल्कि उन्हें एक खास मकसद से होटल में रखा गया है। यह व्यवस्था भावी मेयर चुनाव से पहले पार्षदों को प्रशिक्षित करने के लिए की गई है।

प्रवक्ता शीतल म्हात्रे ने बताया कि होटल में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित पार्षदों को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के कामकाज, उसके नियमों और विनियमों से अवगत कराना है। उन्हें यह भी सिखाया जाएगा कि बैठकों में कैसे भाग लें और विभिन्न मुद्दों पर अपने सवाल प्रभावी ढंग से कैसे उठाएं।

इस कार्यशाला के दौरान, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वयं पार्षदों से मुलाकात करेंगे। वे उन्हें नगर निगम के दायित्वों और लक्ष्यों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। यह पहल यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि सभी नवनिर्वाचित पार्षद अपने कर्तव्यों को कुशलता से निभा सकें।

उद्धव के बयान ने बढ़ाई टेंशन

गौरतलब है कि बीएमसी चुनाव के नतीजों में भाजपा और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गठबंधन ने 227 सदस्यीय निगम में स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। भाजपा को 89 और शिंदे गुट को 29 सीटें मिली थीं। इसके बावजूद, उद्धव ठाकरे ने अगले मेयर को लेकर सस्पेंस बरकरार रखते हुए कहा था कि अगर 'देवा' (भगवान) की इच्छा हुई, तो महापौर उनकी पार्टी का भी हो सकता है। यह उनका मुंबई में शिवसेना (उबाठा) का महापौर बनाने का सपना है।

आईएनएस सागरध्वनि सागर मैत्री V के लिए रवाना

(जीएनएस)।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी (एनपीओएल) का भारत का समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत आईएनएस सागरध्वनि, 17 जनवरी 2026 को दक्षिणी नौसेना कमान, कोच्चि से सागर मैत्री (रट-5) पहल के पांचवें संस्करण के लिए रवाना हुआ।

इस पोत को माननीय संसद सदस्य और रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री राधा मोहन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के माननीय सदस्य, डॉ. समीर वी. कामत, सचिव, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और अध्यक्ष डीआरडीओ; रियर एडमिरल उपल कुंडू, चीफ ऑफ स्टाफ, दक्षिणी नौसेना कमान; डॉ. आर. वी. हारा प्रसाद, महानिदेशक (नौसेना प्रणाली और सामग्री); और डॉ. दुव्वुरी शेषागिरी, निदेशक, एनपीओएल के साथ भारतीय नौसेना और डीआरडीओ के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

सागर मैत्री भारतीय नौसेना और डीआरडीओ की प्रमुख सहयोगी पहल है, जो भारत सरकार के 'क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और समग्र उन्नति (टअलअरअक्षअफ)' के विजन के अनुरूप है। इस पहल का उद्देश्य हिंद महासागर रिम (आईओआर) देशों के बीच सामाजिक-आर्थिक पहलुओं में घनिष्ठ सहयोग और विशेष रूप से समुद्र अनुसंधान में अधिक वैज्ञानिक बातचीत को बढ़ावा देना है।

नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी (एनपीओएल), कोच्चि, आईओआर देशों के बीच वैज्ञानिक सहयोग और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के उद्देश्य से सागर मैत्री कार्यक्रम के तहत समुद्र विज्ञान मिशन चला रही है। इस कार्यक्रम के तहत, डीआरडीओ ने समुद्र अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में आईओआर देशों के साथ दीर्घकालिक सहयोग स्थापित करने के लिए ' मैत्री' टअक्ळफक्र यानी मरीन एंड एलाइड इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इनिशिएटिव)' नामक वैज्ञानिक घटक शुरू किया है।

सागर मैत्री कार्यक्रम के तहत, आईएनएस सागरध्वनि आईएनएस कृष्णा के ऐतिहासिक रास्तों पर फिर से चलेगी, जिसने 1962-65 के दौरान अंतरराष्ट्रीय हिंद महासागर अभियान में हिस्सा लिया था। इस पहल का उद्देश्य आठ आईओआर देशों, यानी ओमान, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और म्यांमार के साथ लगातार वैज्ञानिक सहयोग करना है। यह मिशन मालदीव के साथ सहयोगी समुद्र विज्ञान अध्ययनों की शुरूआत करता है, जिससे आईओआर देशों के वैज्ञानिकों के बीच संयुक्त अनुसंधान और पेशेवर आदान-प्रदान संभव होगा।

सागर मैत्री भारतीय नौसेना के लिए प्रासंगिक अंडरवाटर डोमेन अवेयरनेस (यूडीए) हासिल करने की दिशा में डीआरडीओ के प्रयासों का मुख्य केंद्र है। इन मिशनों के दौरान, डीआरडीओ के अनुसंधान पोत आईएनएस सागरध्वनि द्वारा तय किए गए ऑब्जर्वेशनल ट्रैक पर महत्वपूर्ण समुद्र विज्ञान और ध्वनिक डेटा इकट्ठा किया जाता है, जो यूडीए से संबंधित नियोजित वैज्ञानिक उद्देश्यों के अनुरूप होता है।

आईएनएस सागरध्वनि विशेष समुद्री ध्वनिक अनुसंधान पोत है जिसे एनपीओएल ने डिजाइन किया है और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) ने बनाया है। जुलाई 1994 में कमीशन किया गया यह जहाज तीन दशकों से अधिक समय से समुद्री अवलोकन और समुद्री अनुसंधान के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में काम कर रहा है, जिसने भारत की समुद्री वैज्ञानिक क्षमताओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

रक्षा राज्य मंत्री ने गणतंत्र दिवस शिविर 2026 में एनसीसी कैडेटों से बातचीत की

'आप भारत के गौरवशाली अतीत और उसके उज्ज्वल भविष्य के बीच जीवंत सेतु हैं' - आरआरएम ने कैडेटों से कहा

(जीएनएस)।

रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने 18 जनवरी, 2026 को दिल्ली छावनी स्थित राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) गणतंत्र दिवस शिविर (आरडीसी) का दौरा किया। उनके आगमन पर, एनसीसी कैडेटों ने उन्हें 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया जिसके बाद ग्वालियर के सिंधिया स्कूल के कैडेटों ने एक शानदार बैंड प्रस्तुति दी।

अधिकारियों और कैडेटों को संबोधित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस केवल एक राष्ट्रीय त्योहार नहीं, बल्कि संविधान और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि है। एनसीसी कैडेटों की भूमिका के बारे में बोलते हुए उन्होंने एनसीसी कैडेटों को भारत के गौरवशाली अतीत और उज्ज्वल भविष्य के बीच एक जीवंत सेतु बताया और गणतंत्र दिवस शिविर को भारत के युवाओं के अनुशासन, प्रतिबद्धता और नेतृत्व क्षमता का प्रतिबिंब बताया। उन्होंने कैडेटों को स्वदेशी

सोच के साथ स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के चलते पिछले दशक में भारतीय स्टार्टअपों की संख्या में 800 से बढ़कर 2 लाख से अधिक होने का उदाहरण दिया।

श्री संजय सेठ ने वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन में भाग लेने वाले 15 कैडेटों की सराहना की जिन्होंने रांची से दिल्ली तक 1300 किलोमीटर की दूरी तय करके राष्ट्रीय एकता और वीर बिरसा मुंडा के मूल्यों का प्रसार किया। उन्होंने 2025 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले 10 एनसीसी कैडेटों की भी प्रशंसा की।

अपने समापन भाषण में, रक्षा राज्य मंत्री ने कैडेटों से भविष्य की चुनौतियों का सामना करते हुए कर्तव्य, देशभक्ति और संवैधानिक मूल्यों के प्रति दृढ़ रहने का आग्रह किया और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए इस संकल्प और कड़ी मेहनत को आगे बढ़ाने का आ'ान किया। उन्होंने भावी पीढ़ी के नेतृत्व को आकार देने के लिए एनसीसी के अधिकारियों और प्रशिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया। तिरंगे के सम्मान और गरिमा को बनाए रखने का आ'ान करते हुए, उन्होंने एक मजबूत और अधिक समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में ईमानदारी के साथ निरंतर सेवा करने की अपील की।

इस दौरे के हिस्से के रूप में, आरआरएम ने 'फ्लैग एरिया' का भी दौरा किया, जिसे सभी 17 निदेशालयों के कैडेटों ने विभिन्न सामाजिक जागरूकता विषयों पर सावधानीपूर्वक तैयार किया और उन्होंने 'हॉल ऑफ फेम' का भी दौरा किया, जहां कैडेटों ने एनसीसी के गौरवशाली इतिहास, प्रशिक्षण गतिविधियों और उपलब्धियों के बारे में बताया।

विद्युत वितरण कंपनियों ने वर्षों के घाटे के बाद सकारात्मक लाभ प्राप्ति किया; यह एक नए अध्याय की शुरूआत है : विद्युत मंत्री

वितरण क्षेत्र में कई पहलों से प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों में सुधार हुआ है

(जीएनएस)।

देश की विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम और विद्युत विभाग) ने वित्त वर्ष 2024-25 में सामूहिक रूप से 2,701 करोड़ रुपये का सकारात्मक कर पश्चात लाभ (पीएटी) प्राप्त किया है। यह इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राज्य विद्युत बोर्डों के विभाजन और निगमीकरण के बाद से पिछले कई वर्षों से वितरण कंपनियां समग्र रूप से पीएटी घाटे में चल रही थी।

वित्त वर्ष 2024-25 में 2,701 करोड़ रुपये का सकारात्मक लाभ (पीएटी) दर्ज किया गया जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में 25,553 करोड़ रुपये का घाटा और वित्त वर्ष 2013-14 में 67,962 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

इस पर टिप्पणी करते हुए केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि यह वितरण क्षेत्र के लिए एक नया

अध्याय है और वितरण क्षेत्र की चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए कई प्रयासों का परिणाम है।

मंत्री महोदय ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और दूरदर्शिता के कारण संभव हुई है। उन्होंने इसे अपने शब्दों में व्यक्त किया हैः ह्भारत न केवल अपनी बल्कि विश्व की भी विकास यात्रा को गति दे रहा है। जिसमें ऊर्जा क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।'

श्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र में आवश्यक सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है ताकि विद्युत क्षेत्र हमारी बढ़ती अर्थव्यवस्था को सहयोग दे सके और विकसित भारत की दिशा में अपना योगदान दे सके।

वितरण क्षेत्र में पहलें

वितरण क्षेत्र में किए गए कुछ परिवर्तनकारी पहलों में निम्नलिखित शामिल हैंः

पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस): अवसंरचना के आधुनिकीकरण और त्वरित स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ाना।

अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंडः वित्तीय और परिचालन अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए विद्युत क्षेत्र की उपयोगिताओं के लिए वित्त तक पहुंच को प्रदर्शन मानकों के उपलब्धि से जोड़ना।

विद्युत नियमों में संशोधनः पूर्ण लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए समय पर लागत समायोजन, विवेकपूर्ण शुल्क संरचना और पारदर्शी अनुदान लेखांकन को लागू करना।

विद्युत वितरण (लेखा एवं अतिरिक्त प्रकटीकरण) नियम, 2025: बेहतर वित्तीय संचालन के लिए वितरण उपयोगिताओं में एकसमान लेखांकन और पारदर्शिता बढ़ाना।

भारतीय रेलवे ने ट्रैक के आधुनिकीकरण और सुरक्षा में महत्वपूर्ण प्रगति की है

निरंतर निवेश से रेल सुरक्षा मजबूत हुई है, 2024-25 में 6,851 किमी ट्रैक के नवीनीकरण का कार्य पूरा हो चुका है और 7,500 किमी से अधिक ट्रैक पर काम जारी है और अगले दो वर्षों में 7,900 किमी ट्रैक की योजना बनाई गई है, जिससे कार्यों में तेजी आई है

उच्च गति क्षमता वाले ट्रैक की लंबाई 2014 में 31,445 किमी से बढ़कर अब लगभग दोगुनी होकर 84,244 किमी हो गई है, जिससे राष्ट्रीय रेल नेटवर्क के लगभग 80 प्रतिशत हिस्से पर 110 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति से परिचालन संभव हो गया है

(जीएनएस)।

भारतीय रेलवे ने पिछले ग्यारह वर्षों में निरंतर निवेश और सुनियोजित क्रियान्वयन के माध्यम से अपनी पटरी अवसंरचना को मजबूत करने और सुरक्षा मानकों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इन प्रयासों से देश भर में रेल संचालन अधिक सुरक्षित, तेज और विश्वसनीय हो पाया है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, भारतीय रेलवे ने 6,851 किलोमीटर से अधिक पटरियों का नवीनीकरण किया। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में, 7,500 किलोमीटर से अधिक पटरियों के नवीनीकरण का कार्य जारी है। इसके अतिरिक्त, 2026-27 में 7,900 किलोमीटर पटरियों के नवीनीकरण की योजना है। यह परिसंपत्तियों की विश्वसनीयता और सुरक्षा पर निरंतर जोर को दर्शाता है।

रेलगाड़ियों की सुचारू आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण विस्तारित रेल मार्ग के नवीनीकरण में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 2024-25 में 7,161 थिक वेब स्विच और 1,704 वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग स्थापित किए गए। 2025-26 में 8,000 से अधिक थिक वेब स्विच और 3,000 से अधिक वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग स्थापित किए जा रहे हैं।

पटरी की स्थिरता बनाए रखने और सवारी की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक गिट्टी की मशीनीकृत गहन जांच लगातार की जा रही है। 2024-25 के दौरान 7,442 किलोमीटर पटरी की गहन जांच पूरी की गई, जबकि 2025-26 में 7,500 किलोमीटर से अधिक पटरी की गहन जांच का काम जारी है।

भारतीय रेलवे ने यंत्रीकृत रखरखाव को बढ़ावा देने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपने ट्रैक मशीन बेड़े का काफी विस्तार किया है। 2014 से अब तक 1,100 से अधिक ट्रैक मशीनें खरीदी जा चुकी हैं जिससे रेलवे नेटवर्क का रखरखाव तेज और अधिक कुशल तरीके से हो सकेगा।

रेलवे पटरी के किनारे सुरक्षा बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है ताकि मवेशियों के कुचले जाने और पटरियों पर अनाधिकृत प्रवेश की घटनाओं को कम किया जा सके और समग्र सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। अब तक लगभग 15,000 किलोमीटर की बाड़ लगाई जा चुकी है, जिससे उन खंडों पर सुरक्षा में सुधार हुआ है जहां ट्रेनें 110 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं।

इन निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, भारतीय रेलवे ने पटरियों के उन्नयन में उल्लेखनीय प्रगति की है। 110 किमी प्रति घंटे और उससे अधिक की गति क्षमता वाली पटरियों की लंबाई 2014 में 31,445 किलोमीटर (नेटवर्क का लगभग 40 प्रतिशत) से बढ़कर वर्तमान में 84,244 किलोमीटर (नेटवर्क का लगभग 80 प्रतिशत) हो गई है जिससे ट्रेनों का संचालन तेज और अधिक कुशल हो गया है।

इंडियास्किल्स 2025-26: पूर्वोत्तर क्षेत्रीय प्रतियोगिता 19-22 जनवरी तक असम के गौहाटी विश्वविद्यालय में आयोजित की जाएगी

(जीएनएस)।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा 19 से 22 जनवरी 2026 तक गौहाटी विश्वविद्यालय में इंडियास्किल्स 2025-26 की पूर्वोत्तर क्षेत्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता भारत के राष्ट्रीय स्किलिंग इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। यह पहली बार है कि एक समर्पित इंडियास्किल्स क्षेत्रीय प्रतियोगिता विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आयोजित की जा रही है, जिसमें सभी आठ उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों की भागीदारी है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) इंडियास्किल्स प्रतियोगिता 2025-26 के लिए नॉलेज पार्टनर और इम्प्लीमेंट एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। यह प्रतियोगिता सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों के कुशल युवाओं को क्षेत्रीय प्रतिभा और उत्कृष्टता का जश्न मनाने वाले राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर 26 स्किल कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक साथ लाएगी।

इस प्रतियोगिता का उद्घाटन 19 जनवरी 2026 को भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयन्त चौधरी द्वारा किया जाएगा। यह देश के उभरते क्षेत्रों में कौशल विकास, क्षेत्रीय समावेशन और

प्रतिस्पर्धी उत्कृष्टता को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती हेना उस्मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय प्रतियोगिता उभरते हुए क्षेत्रों में भारत के स्किलिंग आर्किटेक्चर को गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इंडियास्किल्स देश की प्रमुख राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता फ्रेमवर्क है, जिसे विश्व कौशल प्रतियोगिता सहित जमीनी स्तर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफार्मों तक कुशल युवाओं के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रेस पाथवे तैयार करते हुए, वैश्विक मानकों के अनुसार भारत की सर्वश्रेष्ठ वोकेशनल टैलेंट को पहचानने, बढ़ावा देने और बेंचमार्क करने के लिए डिजाइन किया गया है। चल रही इंडियास्किल्स प्रतियोगिता 2025-26 में अब तक की सबसे व्यापक भागीदारी देखी गई है, जिसमें स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 63 स्किल कैटेगरी में 3.65 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।

यह प्रतियोगिता 19 जनवरी को एक परिचय कार्यक्रम के साथ शुरू होगी, जिसके बाद बी.के.बी ऑडिटोरियम, गौहाटी विश्वविद्यालय में उद्घाटन समारोह होगा। इस क्षेत्रीय प्रतियोगिता को प्रतिभागियों के लिए भौगोलिक और लॉजिस्टिकल रुकावटों को कम करने, पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्किल इकोसिस्टम को मजबूत करने और इंडस्ट्री की मांग और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के हिसाब से क्षेत्र-विशिष्ट को मजबूती देने और उच्च-क्षमता वाले उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए बनाया गया है।

महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य को समर्पित पहलए रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल में हाइजीन किट एवं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम

(जीएनएस)। लखनऊ स्थित रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल में गुड हेल्थ केयर सोसायटी एवं समाधान फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य सशक्तिकरण को लेकर हाइजीन किट वितरण एवं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का प्रभावशाली आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को स्वच्छता, टीकाकरण एवं बच्चों की समुचित देखभाल के प्रति जागरूक कर समाज में स्वस्थ भविष्य की नींव रखना रहा।

कार्यक्रम में डॉ. सईका, डॉ. शशि, रश्मि रायजादा, रुकैय्या, ममता जी, पवन सोनी जी एवं कृष्णा प्रजापति की गरिमामयी उपस्थिति रही। विशेषज्ञों द्वारा महिलाओं को टीकाकरण की अनिवार्यता, व्यक्तिगत स्वच्छता (हाइजीन अवेयरनेस) तथा बच्चों के पोषण, देखभाल और रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गईं, जिससे वे अपने बच्चों को एक स्वस्थ, सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य प्रदान कर सकें।

इस अवसर पर गुड हेल्थ केयर सोसायटी की संस्थापक निदा फातिमा ने रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल की सुपरिटेंडेंट नीलिमा सोनकर जी का विशेष आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन एवं सहयोग से कार्यक्रम को सुव्यवस्थित एवं सफल रूप से संपन्न किया जा सका।

कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए अत्यंत आवश्यक बताया। गुड हेल्थ केयर सोसायटी एवं समाधान फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से यह जनहितकारी कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जो महिला एवं बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक सार्थक कदम सिद्ध होगा।

'5-7 साल जेल में रखकर कौन देगा जवाब, जुर्म साबित नहीं तो जमानत आरोपी का हक', उमर खालिद पर पूर्व सीजेआई का बयान

(जीएनएस)। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जमानत व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर ऐसा सवाल खड़ा किया है, जिसने पूरी कानूनी बहस को फिर से तेज कर दिया है। जयपुर साहित्य उत्सव में उमर खालिद केस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक अपराध साबित न हो, तब तक किसी भी आरोपी को जेल में रखना न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में वरिष्ठ पत्रकार वीर संघवी से बातचीत के दौरान पूर्व उखक ने कहा कि भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की नींव इस सिद्धांत पर है कि हर व्यक्ति तब तक निर्दोष है, जब तक अदालत उसे दोषी साबित न कर दे। उन्होंने साफ कहा कि प्री ट्रायल हिरासत किसी भी हालत में सजा का विकल्प नहीं हो सकती। चंद्रचूड़ ने सवाल उठाया कि अगर कोई व्यक्ति 5 या 7 साल अंडरट्रायल के रूप में जेल में बिताता है और बाद में बरी हो जाता है, तो उस खोए हुए समय की भरपाई कौन करेगा।

उमर खालिद केस पर क्या बोले डीवाई चंद्रचूड़?

उमर खालिद केस पर सवाल पूछे जाने पर चंद्रचूड़ ने साफ किया कि वे अब जज के तौर पर नहीं, बल्कि एक नागरिक के रूप में अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि अपनी ही संस्था की आलोचना करना उनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि एक साल पहले तक वे सुप्रीम कोर्ट का नेतृत्व कर रहे थे।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने जमानत के सिद्धांत को बेहद सरल शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा कि जमानत सिर्फ तीन स्थितियों में रोकी जा सकती है। पहला, अगर आरोपी बाहर आकर दोबारा गंभीर अपराध कर सकता हो। दूसरा, अगर सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका हो। तीसरा, अगर आरोपी फरार हो सकता हो।

इन परिस्थितियों के अलावा जमानत को रोकना न्याय के खिलाफ है।

चंद्रचूड़ ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े कानून कई बार निर्दोषता की जगह गिल्ट को प्राथमिकता देने लगते हैं। अदालतों की जिम्मेदारी है कि वे जांचें कि क्या मामला वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और क्या हिरासत जरूरी और अनुपातिक है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह संतुलन नहीं बना, तो लोग बिना सजा के सालों तक जेल में पड़े रहेंगे।

स्पीड ट्रायल नहीं तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन

पूर्व सीजेआई ने कहा कि अगर किसी मामले में ट्रायल समय पर पूरा नहीं हो रहा है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले त्वरित न्याय के अधिकार का सीधा उल्लंघन है।

'मुस्लिम हूं काम नहीं मिल रहा' कहने के बाद अब बोले रहमान, कहा- भारत मेरा घर, गुरु और पहचान

(जीएनएस)। ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान लगातार अपने विवादित बयान की वजह से ट्रोल हो रहे हैं तो वहीं अब रहमान ने सामने से आकर इस मसले पर सफाई दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करके कहा है कि 'संगीत हमेशा से संस्कृति से जुड़ने, उसका जश्न मनाने और उसका सम्मान करने का मेरा तरीका रहा है। भारत मेरी प्रेरणा है, मेरा गुरु है और मेरा घर है।'

आपको बता दें कि रहमान ने अपने शब्दों को गलत समझे जाने पर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा 'मैं समझता हूं कि इरादों को कभी-कभी गलत समझा जा सकता है लेकिन मेरा मकसद हमेशा संगीत के माध्यम से उत्थान करना, सम्मान करना और सेवा करना रहा है।'

'मैंने कभी किसी को दुख पहुंचाने की कोशिश नहीं की और मुझे उम्मीद है कि मेरी ईमानदारी लोगों को जरूर महसूस होगी।' रहमान ने ऐसे माहौल में काम करने को सौभाग्य बताया जहां विविधता और रचनात्मक स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि' उन्हें एक भारतीय के रूप में बहुसांस्कृतिक आवाजों से जुड़ने का अवसर मिला, जिसके लिए वो खुद को लकी मानते हैं।'

अफ फैंल्ल ने अपनी जर्नी के बारे में बात की

अपनी कलात्मक यात्रा का जिक्र करते हुए, रहमान ने कई अहम परियोजनाओं की जानकारी दी, जिसमें प्रधानमंत्री के सामने वेव समिट में 'झाला' और 'रूह-ए-नूर', युवा नागा संगीतकारों संग ऑर्केस्ट्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 'मेरे लिए संगीत ऐसा काम है जो अतीत का सम्मान करता है, वर्तमान का जश्न मनाता है और भविष्य के लिए प्रेरित करता है।'

अफ फैंल्ल पर 'विक्टिम कार्ड' खेलने का आरोप

यह विवाद बीबीसी एशियन नेटवर्क को दिए एक साक्षात्कार से उपजा था, जिसमें रहमान ने कहा था 'पिछले 8 सालों से उन्हें काम नहीं मिल रहा है शायद इसके पीछे कारण साम्प्रदायिक हो सकते हैं।ट

जिस पर बवाल मच गया और आम से लेकर खास तक ए आर रहमान पर उबल पड़े। कुछ लोगों ने उन पर नफरत फैलाने का आरोप लगा दिया तो वहीं किसी ने उन्हें 'पाखंडी' कह दिया है तो वहीं कुछ लोगों ने उन पर 'विक्टिम कार्ड' खेलने का आरोप भी लगाया है।

अफ फैंल्ल को मिले दो ऑस्कर अवॉर्ड

बता दें कि ए आर रहमान का जन्म एक संगीत परिवार में हुआ। उनके पिता आर. के. शेखर दक्षिण भारतीय फिल्मों में संगीतकार थे।

योगी सरकार का 'मास्टरस्ट्रोक'! होटल-रेस्टोरेंट में खाना परोसने वालों की होगी टीबी जांच

(जीएनएस)। उत्तर प्रदेश को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के संकल्प के साथ योगी सरकार ने एक बड़ा सुरक्षा कवच तैयार किया है। सरकार ने अब प्रदेश के सभी होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए नियमित टीबी जांच को अनिवार्य कर दिया है।

शनिवार को हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में इस 'टीबी मुक्त भारत अभियान' के तहत यह अहम फैसला लिया गया। योगी सरकार का मानना है कि पब्लिक डीलिंग और खाने-पीने से जुड़े क्षेत्रों में संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा होता है।

नए नियमों के मुताबिकः

हास्पिटैलिटी सेक्टरः शहरी क्षेत्रों के सभी रेस्टोरेंट और होटलों के स्टाफ की स्क्रीनिंग जरूरी होगी।

मेडिकल कॉलेज व अस्पतालः सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों के छात्रों के साथ-साथ अस्पतालों की रसोई में काम करने वाले कर्मचारियों की भी अनिवार्य जांच होगी।

शुरूआती पहचानः इस कदम से टीबी के लक्षणों को प्रारंभिक स्तर पर ही पहचान कर संक्रमण को फैलने से रोका जा सकेगा।

अपर मुख्य सचिव के सख्त निदेर्शः 'सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं'

बैठक में अपर मुख्य सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) अमित कुमार घोष ने स्पष्ट किया कि टीबी उन्मूलन केवल स्वास्थ्य विभाग का काम नहीं है। उन्होंने निर्देश दिए किः

1.मंथली मीटिंगः राज्य और जिला टीबी फोरम की हर महीने बैठक अनिवार्य होगी।

2.पोर्टल अपडेटः जिला टीबी फोरम की रिपोर्ट को नियमित रूप से सरकारी पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

3.समयबद्ध उपचारः संदिग्ध मरीजों की जांच में देरी न हो और चिह्नित मरीजों को तुरंत वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट दिया जाए।

सोशल मीडिया और 'टीबी चैंपियंस' का सहारा

सरकार अब समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए 'टीबी चैंपियंस' (जो टीबी को हरा चुके हैं) की मदद लेगी। इंटरनेट मीडिया और अन्य संचार माध्यमों के जरिए जागरूकता अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। बैठक में महानिदेशक डॉ. रतन पाल सिंह सुमन और राज्य क्षय रोग अधिकारी डॉ. शैलेंद्र भटनागर समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

बिहार में गूंजेगा यूपी का विजन! पटना में रवि किशन करेंगे योगी सरकार का प्रतिनिधित्व

(जीएनएस)। उत्तर प्रदेश दिवस-2026 के मौके पर योगी सरकार देशभर में अपनी विकास यात्रा और सांस्कृतिक विरासत को सामने रखने जा रही है। इसी कड़ी में बिहार की राजधानी पटना में होने वाला राज्य स्तरीय आयोजन खास रहने वाला है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सांसद रवि किशन प्रदेश का पक्ष रखेंगे।

उत्तर प्रदेश दिवस-2026 के अवसर पर राज्य सरकार ने देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। इन आयोजनों के जरिए उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों, नीतियों और सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा।

24 जनवरी को पटना में दिखेगा यूपी का प्रतिनिधित्व

इसी क्रम में 24 जनवरी को बिहार की राजधानी पटना में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में गोरखपुर से सांसद और प्रसिद्ध अभिनेता रवि किशन शुक्ला योगी सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। वह उत्तर प्रदेश की विकास गाथा को बिहार की धरती से साझा करेंगे।

विभिन्न राज्यों के लिए नामित किए गए प्रतिनिधि

राज्य सरकार ने उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों, सांसदों, विधान परिषद सदस्यों और आयोगों के उपाध्यक्षों को अलग-अलग राज्यों में उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया है। इसका उद्देश्य प्रदेश की नीतियों और उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर प्रस्तुत करना है।

गर्व की बात है यूपी की विकास यात्रा साझा करनाः रवि किशन

इस मौके पर सांसद रवि किशन ने कहा कि गोरखपुर का सांसद होने के नाते बिहार की धरती से उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को साझा करना उनके लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश निवेश, रोजगार और सुशासन के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।

निवेश से डिजिटल गवर्नेंस तक यूपी की बड़ी उपलब्धियां

रवि किशन ने बताया कि उत्तर प्रदेश ने निवेश, रोजगार, स्टार्टअप, एक्सप्रेसवे, मेडिकल शिक्षा, डिजिटल गवर्नेंस और सामाजिक कल्याण योजनाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। इन उपलब्धियों को कार्यक्रम के माध्यम से विस्तार से प्रस्तुत किया जाएगा।

संस्कृति, ओडीओपी और सम्मान समारोह होंगे आकर्षण

उत्तर प्रदेश दिवस-2026 के तहत आयोजित कार्यक्रमों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, नाट्य मंचन, संगीत और नृत्य के साथ-साथ ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान और विश्वकर्मा श्रम सम्मान से सम्मानित किया जाएगा।

यूपी-बिहार के रिश्तों को मिलेगी नई मजबूती

रवि किशन ने प्रदेशवासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह आयोजन उत्तर प्रदेश और बिहार के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंधों को और अधिक मजबूत करने का काम करेगा।

'देश तबाही की ओर है, संविधान बचा लीजिए', सीजेआई के सामने ममता बनर्जी ने क्यों कहा?

(जीएनएस)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने न्यायपालिका से लोकतंत्र और संविधान को "तबाही" से बचाने की अपील की है। जलपाईगुड़ी में सर्किट बेंच के उद्घाटन के दौरान, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की मौजूदगी में उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों पर लोगों को बदनाम करने का आरोप लगाया।

यह बयान आई-पैक कार्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी के बाद आया है, जिसे ममता ने आगामी 2026 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के गोपनीय दस्तावेजों को जब्त करने की साजिश करार दिया। उन्होंने मीडिया ट्रायल और एजेंसियों के दुरुपयोग पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

संविधान और न्यायपालिका को बचाने की अपील

ममता बनर्जी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और अन्य जजों से आग्रह किया कि वे देश के संविधान, लोकतंत्र और इतिहास की रक्षा करें। उन्होंने वर्तमान स्थितियों को "तबाही" जैसा बताते हुए कहा कि न्यायपालिका ही अंतिम रक्षक है। ममता ने स्पष्ट किया कि एजेंसियां जानबूझकर लोगों की छवि खराब करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने न्यायपालिका से आग्रह किया कि वे देश को ऐसे संकट से बचाएं जहां संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा दांव पर लगी हुई है।

हाल ही में ईडी ने राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आई-पैक (I-PAC) के साल्ट लेक ऑफिस और उसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी (क्-ढअउ एऊ १़ࣿ ही२३ ईल्लॅ') की थी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि इस छापेमारी का असली उद्देश्य तृणमूल कांग्रेस के आंतरिक दस्तावेज और 2026 के विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की सूची जैसे संवेदनशील डेटा को हथियाना था। ममता खुद प्रतीक जैन के घर पहुंचीं और वहां से लैपटॉप व दस्तावेज ले गईं, जिसके बाद ईडी ने उन पर काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है।

मीडिया ट्रायल और एजेंसियों पर तीखा हमला

मुख्यमंत्री ने 'मीडिया ट्रायल' की बढ़ती प्रवृत्ति पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मामला अदालत में सुलझने से पहले ही मीडिया लोगों को दोषी ठहराने लगता है, जो एक खतरनाक चलन है। ममता के अनुसार, केंद्रीय एजेंसियां निष्पक्ष काम करने के बजाय राजनीतिक प्रतिशोध के तहत लोगों को बदनाम करने का एजेंडा चला रही हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए किया जा रहा है।

फास्ट-ट्रैक कोर्ट और केंद्र से फंडिंग का मुद्दा

ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि केंद्र ने पश्चिम बंगाल में फास्ट-ट्रैक अदालतों के लिए फंडिंग बंद कर दी है। इसके बावजूद, उनकी सरकार ने राज्य में 88 ऐसी अदालतें स्थापित की हैं और अब तक अदालती बुनियादी ढांचे पर ₹1,200 करोड़ से अधिक खर्च किए हैं।

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के घर में चोरी, आधी रात को उड़ा ले गया लाखों रुपए

(जीएनएस)। बीजेपी सांसद और मशहूर गायक मनोज तिवारी के मुंबई स्थित आवास पर चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित उनके फ्लैट से एक पूर्व कर्मचारी ने डुप्लीकेट चाबियों का उपयोग कर कुल 5.40 लाख रुपये की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। यह चोरी एक बार में नहीं, बल्कि दो किश्तों में की गई थी।

मनोज तिवारी के मैनेजर की शिकायत पर अंबोली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से पकड़े गए इस मामले ने सेलिब्रिटी सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं।

आरोपी को किया गया गिरफ्तार

चोरी की वारदात का खुलासा तब हुआ जब दिसंबर 2025 में घर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों ने 15 जनवरी 2026 की रात एक अलर्ट जारी किया। फुटेज में पूर्व कर्मचारी सुरेंद्रकुमार शर्मा डुप्लीकेट चाबियों से अलमारी खोलकर 1 लाख रुपये चुराते हुए साफ नजर आया। पुलिस ने

इस डिजिटल साक्ष्य के आधार पर आरोपी को धर दबोचा। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह जून 2025 में भी 4.40 लाख रुपये चुरा चुका था। आरोपी दो साल पहले ही नौकरी से निकाला जा चुका था।

कैसे दिया वारदात को अंजाम?

मनोज तिवारी के घर चोरी की इस वारदात को बेहद शातिराना तरीके से अंजाम दिया गया। आरोपी सुरेंद्रकुमार शर्मा, जो दो साल पहले उनके यहां काम करता था, उसने नौकरी छोड़ने से पहले घर, बेडरूम और मुख्य अलमारी की डुप्लीकेट चाबियां बनवा ली थीं। इसी की मदद से वह घर में बिना किसी रुकावट के दाखिल होता था। उसने पहली चोरी जून 2025 में की और 4.40 लाख रुपये उड़ा लिए, जिसका उस समय पता नहीं चल सका। आरोपी की हिम्मत बढ़ी और उसने 15 जनवरी 2026 की रात दोबारा अलमारी खोलकर 1 लाख रुपये चुराए, लेकिन इस बार वह उउळश अलर्ट की चपेट में आ गया।

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

मनोज तिवारी के मैनेजर प्रमोद पांडे ने अंबोली पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच में पाया गया कि आरोपी के पास घर और अलमारी की डुप्लीकेट चाबियां मौजूद थीं, जिसका फायदा उठाकर वह आसानी से वारदात को अंजाम दे रहा था। फिलहाल, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए हैं और आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है

कर्मा पर्व प्रकृति से जुड़ाव और सामूहिक आनंद का उत्सवः सीएम साय

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कर्मा महोत्सव सांस्कृतिक उत्सव और सार्वजनिक निवेश का संगम है। नेताओं ने ₹172.51 करोड़ के विकास कार्यों की घोषणा की, जिसमें चुंगरीडी में एक मिनी-स्टेडियम और शहर-स्तरीय उन्नयन शामिल हैं। इस कार्यक्रम में आदिवासी प्रदर्शन और महिलाओं, आजीविका और कल्याणकारी योजनाओं का समर्थन करने वाली पहलें शामिल थीं।

(जीएनएस)। रायपुर, 17 जनवरी 2026। कर्मा महोत्सव छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, परंपरा और लोक जीवन का सजीव प्रतीक है। ऐसे आयोजन न केवल लोक पर्वों को सहेजने का कार्य करते हैं, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। कर्मा पर्व प्रकृति से जुड़ाव, आपसी भाईचारे और सामूहिक आनंद का उत्सव है।

यह विचार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सूरजपुर जिले के चुनगुड़ी में आयोजित कर्मा महोत्सव के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जनजातीय संस्कृति की पहचान और उसकी निरंतरता के लिए ऐसे आयोजन अत्यंत आवश्यक हैं।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सूरजपुर जिले को 172.51 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी। साथ ही चुनगुड़ी के स्कूल मैदान को मिनी स्टेडियम के रूप में विकसित करने और नगर पंचायत भटगांव के विकास के लिए एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की। कार्यक्रम को महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और सांसद चिंतामणि महाराज ने भी संबोधित किया।

परंपरा, संस्कृति और उल्लास से भरे कर्मा महोत्सव में मांदर की थाप और घुंघरुओं की झंकार के बीच पूरा क्षेत्र कर्मा नृत्य की लय में झूम उठा। सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर, कोरिया और मनेंद्रगढ़ जिलों से आए 33 कर्मा दलों के लोक कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में मनमोहक कर्मा नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों को लोक संस्कृति के रंगों में रंग दिया।

महिला सशक्तिकरण और कल्याण योजनाओं का शुभारंभ

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई प्रदर्शनी के विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस दौरान नाव-जाल एवं आइस बॉक्स, आयुष्मान कार्ड, छत्तीसगढ़ महिला कोष से ऋण वितरण और महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित छह रेडी-टू-ईट इकाइयों का शुभारंभ किया। उन्होंने पोषण वितरण कार्य से जुड़ी महिलाओं को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही महिलाओं को स्वरोजगार के लिए मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत बीमा क्लेम तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 'खुशियों की चाबी' प्रदान की गई।

जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति

कार्यक्रम में विधायक भूलन सिंह मरावी, वन विकास निगम के अध्यक्ष राम सेवक पैकरा, जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्रमणि पैकरा, उपाध्यक्ष रेखा राजलाल रजवाड़े सहित अनेक जनप्रतिनिधि, जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।